

स्पीडपोस्ट/सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सं०-27011/51/2014-आरएण्डडबल्यू

भारत सरकार गृह मंत्रालय,  
पुलिस-प् डिविजन  
पुनर्वास एवं कल्याण निदेशालय

\*\*\*\*\*

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-01  
दिनांक जुलाई 2014  
14 JUL 2014

सेवा में,

श्री संजय कुमार,, भूतपूर्व हवलदार  
मुहल्ला-गौधी नगर, वार्ड न० 9,  
एस०डी०ओ० निवास, बिकमगंज-802212,  
जिला-रोहतास, बिहार

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन पत्र

कृपया अवर सचिव, आरटीआई सैल, गृह मंत्रालय के कार्यालय  
ज्ञापन संख्या ए-43020/01/2014-आरटीआई दिनांक 04/07/2014 का  
अवलोकन करें जिसके माध्यम से आपके पत्र दिनांक शून्य को अग्रेसित  
किया गया है जो सूचना प्राप्त करने के सम्बन्ध है।

2. उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत करवाया जाता है कि केन्द्रीय सशस्त्र  
पुलिस बल के भूतपूर्व कर्मियों और उनके परिवारों के कल्याण हेतु  
निम्नलिखित योजनाएँ कार्यान्वित की जा रही हैं:-

- प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के आश्रितों को, लड़कियों के लिए रु०2250/-प्रतिमाह और लड़कों के लिए रु० 2000/- प्रतिमाह की दर से उच्च तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी जा रही है।
- बल के कर्मियों एवं उनके परिवारों को वांछित जगहों पर सस्ती दरों पर व्यापाक रेंज और विविध प्रकार की उपभोक्ता वस्तुएँ मुहैया कराने के लिए 18/09/2006 को एक केन्द्रीय पुलिस कैंटीन की स्थापना की गई है।
- निःशक्त कर्मियों सहित केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों और उनके परिवारों के कल्याण एवं पुनर्वास हेतु दिनांक 17/05/2007 को एक कल्याण एवं पुनर्वास बोर्ड (WARB) की स्थापना की गई है। पूरे भारत वर्ष में 06-केन्द्रीय कल्याण अधिकारी, 29-राज्य कल्याण अधिकारी और 137-जिला कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती के स्थान पर की गई है, जिनसे केन्द्र तथा राज्यों द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी याजनाओं की जानकारी के लिए सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी हेतु WARB की वेबसाइट <http://warb-mha.nic.in> देखी जा सकती है।
- इसके अलावा यदि बल के कर्मियों की मृत्यु सक्रिय ड्यूटी के दौरान हुई है तो उदारीकृत पेंशन अवार्ड दिया जाता है जो अन्तिम आहरित वेतन के बराबर है और अन्य मामलों में पारिवारिक पेंशन का प्रावधान है।
- सरकारी अनुदेशों के अनुसार ड्यूटी के दौरान मारे गए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के आश्रितों को नियमानुसार अनुग्रह मुआवजा रु० 10 लाख अथवा 15 लाख दिया जा रहा है।
- ग्रुप ग एवं घ में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु 5 प्रतिशत का आरक्षण भी है।
- भूतपूर्व कर्मिक, पूरे भारत वर्ष में जिन स्थानों पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम (सीजीएचएस) की सुविधा उपलब्ध है, के अन्तर्गत चिकित्सा सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। जहाँ पर यह सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहाँ भूतपूर्व कर्मिक पेंशन के साथ साथ रु० 300/-प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता प्राप्त कर सकते हैं।

लगातार-2

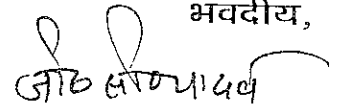


3. उपरोक्त पर विस्तृत जानकारी हेतु Ministry of Home Affairs की website- <http://mha.nic.in> तथा अनुकम्पा के आधार पर भर्ती के सम्बन्ध में Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions की website- <http://persmin.nic.in> भी देखी जा सकती है। उपर्युक्त के अतिरिक्त बलों की अपनी कल्याण योजनाएँ और निधियाँ भी हैं जो जवानों और उनके परिवारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बल के स्तर पर बनाई गई है इनकी विस्तृत जानकारी हेतु सम्बन्धित बल की वेबसाइट देखी जा सकती है।

4. राज्यों द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के सम्बन्ध में सम्बन्धित राज्य सरकारों में नियुक्त केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी से आप सीधे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

5. उपरोक्त के सम्बन्ध में अपील करने की दशा में श्री निर्मलजीत सिंह कलसी, संयुक्त सचिव (पुलिस-II), गृह मंत्रालय, कमरा न० 171-बी, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-01, अपीलेंट अधिकारी है।

भवदीय,

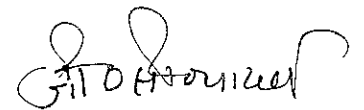


(जी० सी० यादव)

उपसचिव (पीएमए) एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि :-

1	श्री एस० सामंत, अवर सचिव, आरटीआई सैल, गृह मंत्रालय।	- को कार्यालय ज्ञापन दिनांक 04/07/2014 के सन्दर्भ में सूचनार्थ।
2	अनुभाग अधिकारी, आई टी सैल, गृह मंत्रालय	गृह मंत्रालय की वेब साइट पर अपलोड करने हेतु।

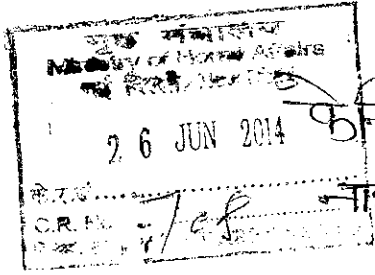


(जी० सी० यादव)

उपसचिव (पीएमए) एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

सेवा में

MUSY/RTS/1111/2014  
30/6/14



कृष्ण गृह सचिव  
नार्थ ब्लॉक नई दिल्ली

**ब्लॉक सूचना पदाधिकारी**

- विषय :- अधिनियम 2005 आर. टी. आई  
भूतपूर्व अर्द्धसैनिक बल कर्मियों को  
केन्द्र सरकार/राज्य सरकार या बल द्वारा  
भिलमें वाली सहायता/दूर संबंधी जानकारी प्राप्त  
करने हेतु

Dir (Pers)  
Per (Pers-1)

महोदय

अधिनियम नाम निवेदन इस प्रकार से है कि  
भूतपूर्व. जी. टी. बलदार बल संख्या. 881140506/ पी. पी. ओ. नं.  
2390309-0832-1 राजेश कुमार का अर्ज प्रकार से है  
जब मैं भूतपूर्व कर्मिक को केन्द्र सरकार/राज्य सरकार या बल द्वारा  
भिन्न-भिन्न तरह की सुहायता, रिहाय/दूर, कल्याण, संबंधी सम  
हित हे लेकिन इस तथ्य, बिना कि आधिकारी नही पौ जानी है  
इसका उपयोग ही अज्ञानता बनी रहती है  
जिसका नतीजा भूतपूर्व कर्मिक अनजान बेसहारा होकर दुर्भाग्य  
वर्ती रहते हैं

- ① अर्जियों को पढें के विधि/रूकन, ऑफिस, के विधि विहित  
एव राशी की प्रकथ कथा है
- ② मेडिकल इलाज हेतु विहित, राशी,
- ③ पुनर्सेवा हेतु प्रबंध
- ④ पुनर्वास हेतु प्रबंध कथा है

राज्य सरकार भूतपूर्व कर्मिकों के विधि व राशी कथा  
कल्याण, प्रबंध दूर रिहाय की अभियोजन किया गया  
अर्जियों की पढें संबंधी  
② मेडिकल इलाज  
③ सेवा हेतु प्रबंध कथा है  
④ पुनर्वास हेतु प्रबंध कथा है

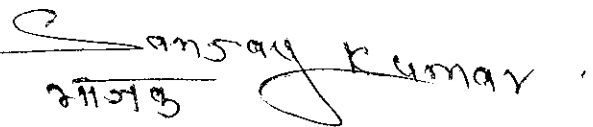
5) किसी लॉटरी या पंगी कूट हैर

— बल मे भूतपूर्व फुर्मिड को - कमा - कमा, कम्पकम्पाना,  
शियात कूट हैर

अंग मधेय से कर्षण प्रार्थना है भूतपूर्व प्रार्थी  
उी सूचना का अधिकार आवेदन पत्र पर अद्यतनजर  
रखते हुये, रूपरत, रणं पारदर्शिता, सूचना देने हेतु  
कृपा नयान कुर

— बल मे अज्ञान का उल्लंघन बना रहता  
है जिसको दुरा विश्वास जाता है या प्रार्थनी नहि किमा  
जाता जिसका लाग नही गिला पाता है

संलग्न 3-P-0 - Rs.10  
NO - 28F - 360214

  
Anshu Kumar  
भोजपुर

भूतपूर्व जीजी हवलदार  
पीपीओ नं० 2390-309-0832  
बल सं- 881140506  
मुहल्ला - गोपी नगर  
वार्ड नं० 9 उ.प.०.मिनास  
पिपुमगंज - 802212  
जिला - रोहतास  
बिहार